मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट

मामले के अध्ययन: निजता का अधिकार

कार्ली निस्ट: द्वारा विकसित

विचार विमर्श के लिए केस अध्ययन

भारत की विशिष्ट पहचान योजना

2009 के बाद से भारत सरकार ने देश के 1.2 अरब नागरिकों के लिए एक अनूठा बायोमेट्रिक पहचान (यूआईडी) दर्ज करने के लिए इस योजना को मूरत रूप प्रदान किया है. यूआईडी व्यक्तिगत पहचान को बायोमीट्रिक डाटा के साथ जोड़ता है उंगलियों के निशान और रेटिना स्कैन के माध्यम से , और हर भारतीय की व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट रूप से पहचाने बनाये जाने के एक सुलभ प्रयास को साकार कर रहा है.

भारत सरकार का मानना है कि यूआईडी उन्हें कानूनी पहचान दे रही है, हर नागरिक को, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वालों को और इसके माध्यम से उनकी दृश्यता बनाने में मदद मिलेगी. यूआईडी से गरीब को माध्यम मिलेगा जिससे वो सरकारी सेवाओं और लाभ का उपयोग कर सकते हैं, और इससे भ्रष्टाचार का सफाया करने में मदद मिलेगी. एक अरब से अधिक लोगों की आबादी के लिए सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करवा पाना एक असंभव काम है जब तक कि सरकार उन लोगों में से हर एक की पहचान करने और उन तक पहुँचने में सक्षम न हो जाये. यूआईडी इस एक दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. यूआईडी प्रणाली के आलोचकों का कहना है कि बजाय शामिल किए जाने के प्रयास हो के, यूआईडी एक अपवर्जनात्मक साधन बनता जा रहा है. भले ही यूआईडी जाहिर तौर पर एक स्वैच्छिक पहल है, कई भारतीय सरकारी विभाग उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवा में एक व्यक्ति को

दाखिला से पहले यूआईडी मांग की कर रहे हैं. बैंक एक खाते को खोलने या बनाए रखने के लिए यूआईडी को वांछनीय दस्तावेज के रूप में मांग सकते हैं. भारतीय नागरिकों को सरकारी योजना में नामांकन के लिए सही दस्तावेजों की आवश्यकता होती है; दुर्भाग्य से, सबसे गरीब और हाशिए पर रहें वाले नागरिकों के पास इस तरह के दस्तावेज ज्यादातर नहीं है. गरीब को चेहरा अन्य बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है; एक स्थायी पते की आवश्यकता; नाम जो शायद ही कभी लिखा गया है की वर्तनी में मतभेद; यहां तक कि एक साधारण सी समस्या जो कि ग्रामीण जीवन में या शहरों में भी मजदूरी करने से हो जाती है उँगलियों के निशान गायब हो जाने के रूप में जिसके कारण उनकी उँगलियों के निशान प्राप्त नहीं हो सकते और उनका यूआईडी बनाने में समस्या आती है. बॉयोमीट्रिक्स की विश्वसनीयता के रूप में पहले से काफी मात्रा में बहस चल रही है. अमेरिका के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद सितंबर 2010 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बॉयोमीट्रिक्स की वर्तमान स्थिति "स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय" है.

केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुंचने से पहले डेटा यूआईडी प्रणाली की स्थापना के दौरान बहुत सारे निजी संस्थाओं से होकर गुजरते हैं, और कई चरणों से होकर अपने गंतव्य तक पहुचने के दौरान कई जगहों पर दिए गए डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता भी जताई जा रही है. केंद्रीय डेटाबेस तक पहुँच जाने के बाद, डेटा का उपयोग करने के बारे में भी चिंता जताई जा रही है क्योंकि यूआईडी डाटाबेस राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड से जुड़ा हुआ है और इसका प्रयोग आबादी की निगरानी करने के लिए भी किया जा सकता है.